राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 236

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, रविवार, 2 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

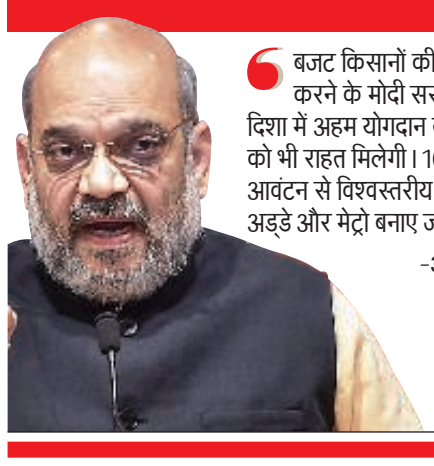

‘बजट किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मोदी सरकार के संकल्प की दिशा में अहम योगदान देगा। करदाताओं को भी राहत मिलेगी। 100 लाख करोड़ के आवंटन से विश्वस्तरीय हाईवे, रेलवे, हवाई अड्डे और मेट्रो बनाए जाएंगे।

–**अमित शाह**, केंद्रीय गृह मंत्री

बड़ी छलांग की ओर सधे कदम

- पीपीपी मॉडल में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, जिला अस्पताल से जुड़ेंगे
- शिक्षा क्षेत्र में एफडीआइ को बढ़ावा स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम शुरू होगा
- अगले साल बंटेगा 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज
- कॉरपोरेट टैक्स 15% किया, सरकार का राजस्व घटेगा, पर नौकरियां बढ़ेंगी

जयप्रकाश रंजन ● नई दिल्ली

भारत के सबसे लंबे बजट भाषण में लोकलुभावन वादों के बजाय अर्थव्यवस्था की वर्तमान जमीनी हकीकत को पहचानते हुए भविष्य का आधार गढ़ने की कोशिश हुई। बजट में अगले एक दशक में अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का रोडमैप पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से अहम सुधारों को आगे बढ़ाते हुए मौजूदा मंदी से निपटने और भविष्य के लक्ष्य को हासिल करने का जज्बा दिखाया है। राजस्व की वस्तुस्थिति समझते हुए सुर्खियां बटोरने वाली घोषणाओं से परहेज किया, लेकिन हर सेक्टर को कुछ न कुछ देने की व्यवस्था की। मध्यम वर्ग को आय कर में राहत दी तो कॉरपोरेट सेक्टर को लाभांश टैक्स से मुक्ति दी। किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए कृषि और इसके सहयोगी क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया तो ग्रामीण क्षेत्र को रिकॉर्ड आवंटन किया। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डीएनए डाटा, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे न्यू इकोनॉमी के नए सेक्टर के जरिए भारत को चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए भी तैयार किया है।

सीतारमण ने बजट पेश करते हुए देश को याद दिलाया कि इसके जरिए पीएम मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ के नारे को आगे बढ़ा रही हैं। मोदी ने आम बजट 2020-21 को जन-जन का बजट करार दिया। विपक्ष को बजट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और शेयर बाजार ने भी 988 अंकों का गोता लगा कर निराशा जताई। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए 15 फीसद के लाभांश वितरण कर को समाप्त करने की घोषणा से भी बाजार खुश नहीं है। वित्त मंत्री को भरोसा है कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो तब वह उनके उपायों को ज्यादा बेहतर समझने की स्थिति में होगा।

एलआइसी में अपनी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार: बजट में 15 लाख रुपये की सालाना आय वाले वर्ग के लिए आयकर की दर में 10 फीसद तक की छूट देने की घोषणा की है, लेकिन शर्त है कि किसी प्रकार का छूट नहीं लेने वाले को ही इसका लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने बड़े आयकर सुधार की दिशा में इसे पहला कदम बताया। आने वाले दिनों में सभी प्रकार के टैक्स रिबेट खत्म होंगे और दरें भी घटेंगी। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) में सरकार ने अपनी इक्विटी घटाने का एलान किया है, जो संभवतः इस बजट का सबसे साहसिक फैसला है। बैंकों में जमा अब पांच लाख रुपये तक की राशि को बीमा कवरेज मिलेगा। अभी यह राशि एक लाख रुपये थी। सहकारी बैंकों को मजबूत करने का एलान है और सरकारी बैंकों के प्रदर्शन में सुधार की कवायद की घोषणा है। कभी सरकारी बैंक रहे आइडीबीआइ में केंद्र की हिस्सेदारी पूरी तरह बेची जाएगी।

भरोसा बढ़ाने की कोशिश >> संपादकीय

न्यूजप्रिंट पर आयात शुल्क घटाकर 5% करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, प्रेट्र : निर्मला सीतारमण ने न्यूजप्रिंट पर आयात शुल्क घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। सरकार ने पिछले साल बजट में न्यूजप्रिंट और हल्के कोटेड कागज पर 10 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाया था। सीतारमण ने कहा, ‘मुझे बताया गया है कि इस शुल्क से मुश्किल समय में प्रिंट मीडिया पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इसी के मद्देनजर मैं न्यूजप्रिंट और हल्के कोटेड कागज पर सीमा शुल्क 10 से घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं।’ इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (आइएनएस) ने इससे पहले सरकार से कहा था कि वह समाचार पत्र उद्योग को बचाने के लिए अखबारों के प्रकाशन में काम आने वाले न्यूजप्रिंट व अनकोटेड कागज और पत्रिकाओं के प्रकाशन में काम आने वाले हल्के कोटेड कागज पर सीमा शुल्क को पूरी तरह समाप्त करे।

आर्थिक माहौल बदलने की मेहनत...सबसे लंबा बजट भाषण

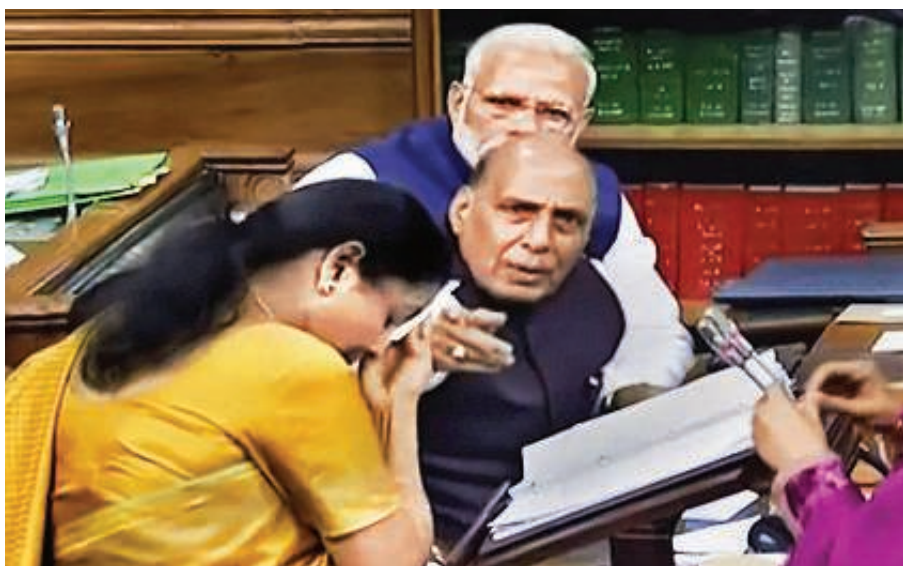

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में आम बजट 2020–21 पेश किया। 2 घंटे 40 मिनट लगातार बजट प्रस्ताव पेश करने के दौरान वह अस्वस्थ महसूस करने लगीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत उनकी खैरियत पूछी ● प्रेट्र

व्यवस्था

- सभी अराजपत्रित पदों पर होंगी ऑनलाइन नियुक्तियां
- सरकार विनिवेश से 1.21 लाख करोड़ रुपये का करेगी इंतजाम
- आइडीबीआइ में सरकार की पूरी इक्विटी बेची जाएगी
- कृषि व ग्रामीण क्षेत्र के आवंटन में कोई कमी नहीं

‘विजन’ और ‘एक्शन’ वाला बजट : प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली : आम बजट को अर्थव्यवस्था में जान डालने वाला बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसमें ‘विजन और एक्शन’ दोनों है। एक तरफ इससे आमदनी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं मांग और खपत भी इजाफा होगा। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व उनकी टीम को बधाई दी।

● पेज 3

बेरोजगारी से लड़ने के कारगर उपाय

बेरोजगारी पर सरकार की सबसे ज्यादा आलोचना होती है। इसके लिए छोटे–छोटे कई उपाय किए हैं। जैसे, भारत को चीन के मुकाबले आकर्षक निर्माण स्थल के तौर पर पेश कर मोबाइल फोन, चिप, सेमीकंडक्टर के निर्माण स्थल के तौर पर स्थापित करने की योजना है। क्वांटम तकनीकी के लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान बड़ा एलान है। चीन से सस्ते आयात पर लगाम लगाने के प्रयास किए हैं।

पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और किसानों का खयाल

पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी और किसानों की आय दोगुनी करना सरकार की दो अहम नीति है। इसके लिए सीधे कोई एलान करने के बजाए संबंधित सेक्टरों को मजबूत बनाने की रणनीति अपनाई है। कृषि व ग्रामीण सेक्टर के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। किसानों के लिए अगले वित्त वर्ष बैंकों से 15 लाख करोड़ रुपये कर्ज मुहैया कराने का एलान किया है।

10 फीसद विकास दर का आकलन

विकास दर पांच फीसद पर पहुंच जाने के बावजूद सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 10 फीसद के नामिनल विकास दर का आकलन किया है। अगले वर्ष के लिए सरकार ने 5.45 लाख करोड़ रुपये उधारी लेने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने बताया कि जीडीपी के मुकाबले देश पर कुल कर्जे का अनुपात मार्च 2019 में 52.2 फीसद था, जो घट कर 48.7 फीसद रह गया है।

ये होगा महंगा

- घी, मक्खन, खाद्य तेल
- छाछ, चीनी, मक्का, संरक्षित आलू
- सोयाबीन
- फुटवियर, हेयर क्लिप, शैम्पू
- अखरोट
- रसोई सामग्री
- कांच का सामान
- माणिक, पन्ना, नीलम
- ताला ● छलनी
- छत और दीवार वाले पंखे
- ब्लोअर, टोस्टर
- हीटर, इमल्शन रॉड
- हेयर ड्रायर, प्रेस
- ग्राइंडर, ओवेन, कुकर,
- लैंप, फर्नीचर
- स्टेशनरी, घंटियां, खिलौने
- मोबाइल फोन

ये होगा सस्ता

- रॉ शुगर ● स्किम्ड मिल्क
- सोया फाइबर ● सोया प्रोटीन
- कृषि–पशु आधारित उत्पाद
- प्यूरीफाइड टेरिफैलिक एसिड
- अखबार का कागज
- कोटेड पेपर

एक्साइज बढ़ाया

- सिगरेट, हुक्का, तंबाकू

एक्साइज घटाया

- खेल का सामान ● माइक्रोफोन
- इलेक्ट्रिक वाहन ● समाचार पत्र

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

3.8% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान। अगले साल के लिए 3.5 फीसद का लक्ष्य। नौकरीपेशा वर्ग के लिए बेहतर पेंशन स्कीम लागू करने की योजना

बड़ी बातें

- पीपीपी मॉडल पर किसान रेल चलाई जाएगी। कृषि उड़ान की शुरुआत भी होगी।
- 10 राष्ट्रीय बैंकों को चार बैंकों में बदलेंगे। इन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश होगी
- 100 करोड़ जी–20 शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए आवंटित। 2022 में मेजबानी करेगा भारत

‘मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। बजट में मैंने ऐसा कोई रणनीतिक विचार नहीं देखा, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले। यह सरकार केवल बातें करती हैं, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है।’

राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

शेयर बाजार नाखुश, 988 अंक लुढ़का सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र : शेयर बाजारों ने बजट पर बेहद ठंडी प्रतिक्रिया दी। वित्त मंत्री द्वारा राजकोषीय घाटे का अनुमान 3.3 से बढ़ाकर 3.8 परसेंट करने की घोषणा के बाद बीएसई और एनएसई के प्रमुख सूचकांकों में बड़ी गिरावट आई। हालांकि, सत्र के अंत में गिरावट पर कुछ ब्रेक लगा। फिर भी इंट्रा-डे में 1,275 अंकों तक टूट चुका बीएसई-सेंसेक्स आखिरी वक्त में थोड़े सुधार के बावजूद 987.96 अंकों की गिरावट टाल नहीं पाया।

कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 39,735.53 के स्तर के साथ 40,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे बंद हुआ। एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 300.25 अंक लुढ़क गया। कारोबार के आखिर में निफ्टी 11,661.85 पर स्थिर हुआ। घरेलू शेयर बाजारों के लिए आमतौर पर शनिवार छुट्टी का दिन होता है, लेकिन बजट के कारण ये शनिवार को खुले थे।

तीव्र गिरावट के चलते बीएसई के निवेशकों को करीब 3.46 लाख करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा। वैसे पिछले बजट की प्रस्तुति से अब तक सेंसेक्स में 222.14 अंक का इजाफा हुआ है, जबकि निफ्टी में 149.30 अंक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स पैक में आइटीसी के शेयरों में सबसे अधिक 6.97 परसेंट की गिरावट आई। आइसीआइसीआइ बैंक, एलएंडटी, एचडीएफसी, एसबीआइ, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक के शेयरों में भी 5.98 परसेंट तक की गिरावट देखी गई।

बजट में शुभ मंगल कराधान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: आम बजट में टैक्स कटौती की बाट जोह रहे आम आदमी के लिए सरकार ने आयकर की घटी हुई दरों के साथ नए स्लैब का प्रस्ताव किया है। इसके तहत 15 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तिगत कर में निचली दर का लाभ ले पाएंगे। लेकिन, इसका लाभ उन्हें मिलेगा जो आयकर अधिनियम के तहत मिलने वाली विभिन्न छूट और राहत का लाभ नहीं लेंगे। नई कर व्यवस्था से सरकार को 40000 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि उठानी होगी।

लोग अब अपनी इच्छा से मौजूदा और नई कर व्यवस्था में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। कोई करदाता नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है तो आगे भी उसी के मुताबिक आयकर का भुगतान करना होगा। सरकार ने पिछले बजट में पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी थी। लेकिन इस वर्ष सरकार ने व्यक्तिगत करदाताओं को पर्याप्त राहत देने और कानूनों को सरल बनाने के लिए नई कर व्यवस्था लाने का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री का मानना है कि नई कर व्यवस्था का ढांचा मध्यम वर्ग के करदाताओं को पर्याप्त राहत देगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में 15 लाख की आमदनी अर्जित करता है और किसी कटौती का लाभ नहीं उठा रहा तो उसे पुरानी व्यवस्था में 2.73 लाख का आयकर अदा करना होता है। यदि वह व्यक्ति नई कर व्यवस्था को अपनाता है तो उसे केवल 1.95 लाख का आयकर ही देना होगा। इस लिहाज से उसे आयकर में 78,000 की बचत होगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि नई कर व्यवस्था में सरकार को 40,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान उठाना होगा। उन्होंने कहा, ‘आयकर प्रणाली को सरल बनाने के लिए विगत में अनेक दशकों में आयकर कानून में समाविष्ट की गई सभी छूटों और कटौतियों का आकलन किया है। आश्चर्य है कि वर्तमान में विभिन्न प्रकार की एक सौ से अधिक छूटें और कटौतियां प्रदान की गई हैं। मैंने नई व्यवस्था में इनमें से 70 को हटा दिया है।’ दरअसल, पिछले दिनों अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार को देखते हुए कॉरपोरेट टैक्स की दरों में हुई कटौती के बाद माना जा रहा था कि सरकार मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर की दरों में भी कमी करेगी।

- **छूट और राहत नहीं लेने वालों के लिए आयकर के नए स्लैब, पहली बार दिया विकल्प**
- **आयकर की दरों में भारी राहत, लेकिन कटौती और छूट का त्याग करने वालों को ही मिलेगा लाभ**
- **15 लाख सालाना आय वालों को नई व्यवस्था में 78000 रुपये की होगी बचत**

कितनी इनकम पर कितना टैक्स

आमदनी	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2020–21
2.5 लाख	0%	0%
2.5–5 लाख	5%	0%
5–7.5 लाख	20%	10%
7.5–10 लाख	20%	15%
10–12.5 लाख	30%	20%
12.5–15 लाख	30%	25%
15 लाख से ज्यादा	30%	30%

शाहीन बाग में धरने के विरोध में चलाई गोली

नई दिल्ली : सीएए और एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग में डेढ़ माह से चल रहे धरने के विरोध में शनिवार को एक युवक ने धरनास्थल के समीप गोली चला दी। (पेज–14)

वुहान से वापस लाए गए 324 भारतीय

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच शनिवार को चीन के वुहान शहर से 324 भारतीयों को एयर इंडिया के विशेष विमान से वापस लाया गया। (पेज–16)

सूचना : बजट की विस्तृत कवरेज के चलते रविवार को प्रकाशित होने वाला मुद्दा और स्पार्क पेज स्थगित किया जा रहा है।

विश्व कप की तैयारी

पांचवां टी–20 भारत vs न्यूजीलैंड

दोपहर 12:30 बजे से

स्थान : माउंट मौंगानुई

प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

...ताकि बढ़े पर्यटन

पांच राज्यों में विकास के लिए 2500 करोड़ रुपये के आवंटन का वित्त मंत्री ने किया प्रस्ताव

अब पुरातात्विक स्थलों के विकास पर जोर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पर्यटन रोजगार के सृजन का बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में जब सरकार ने रोजगार के लिए सोचा तो बजट में पर्यटन का जिक्र हुआ। देश के पांच राज्यों में स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में पांच पुरातात्विक स्थलों के विकास की घोषणा की गई है। इनमें पांच प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास भवन बुनियादी ढांचे का विकास भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे पुराने कोलकाता के भारतीय संग्रहालय के पुनरुद्धार की घोषणा की थी। इसके साथ ही ऐतिहासिक पुराने टकसाल भवन में मुद्रा-विषयक और व्यापार पर एक संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान भी खोलना प्रस्तावित है। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा।

शनिवार को आम बजट में पर्यटन क्षेत्र के लिए 2020-21 में 2500 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये के आवंटन का भी प्रस्ताव किया है। संग्रहालय विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान की विधाओं में अच्छी तरह प्रशिक्षित संसाधनों को विकसित करने के लिए पहला भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस संस्थान का दर्जा मानद विश्वविद्यालय का होगा और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन परिचालित होगा। बजट में घोषणा की गई है कि देश के चार और संग्रहालयों का नवीनीकरण री-क्यूरेशन किया जाएगा, ताकि आगंतुकों को विश्वस्तरीय अनुभूति मिल सके। इसके अलावा मोदी सरकार झारखंड के रांची में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का समर्थन करेगी।

2019 में 34वें पायदान पर पहुंचा : देश में वर्ष 2014 में यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धी सूचकांक (विश्व आर्थिक मंच) में 65वां स्थान था जो 2019 में 34वें पायदान पर पहुंच गया है।

इन पुरातत्व स्थलों का होगा विकास

- राखीगढ़ी (हरियाणा)
- हस्तिनापुर (उत्तर प्रदेश)
- शिवसागर (असम)
- धौलाविरा (गुजरात)
- अदिचनल्लूर (तमिलनाडु)
- देशभर के उन चुनिंदा पर्यटक स्थलों में जिस श्रेणी में लाल किला व ताजमहल आते हैं, अब ये पांचों भी शामिल होंगे।

हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी को भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल माना जाता है ● फाइल फोटो